

संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (JCPOA)

प्रलिस के लयि:

संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (JCPOA), अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA), चाबहार पोर्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांज़िटि कॉरडोर (INSTC), काउंटरगि अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सैकशन्स एक्ट (CAATSA) ।

मेन्स के लयि:

भारत से जुड़े समूह और समझौते और/या भारत के हतियों पर देशों की नीतियों और राजनीतिका प्रभाव, JCPOA और इसका महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

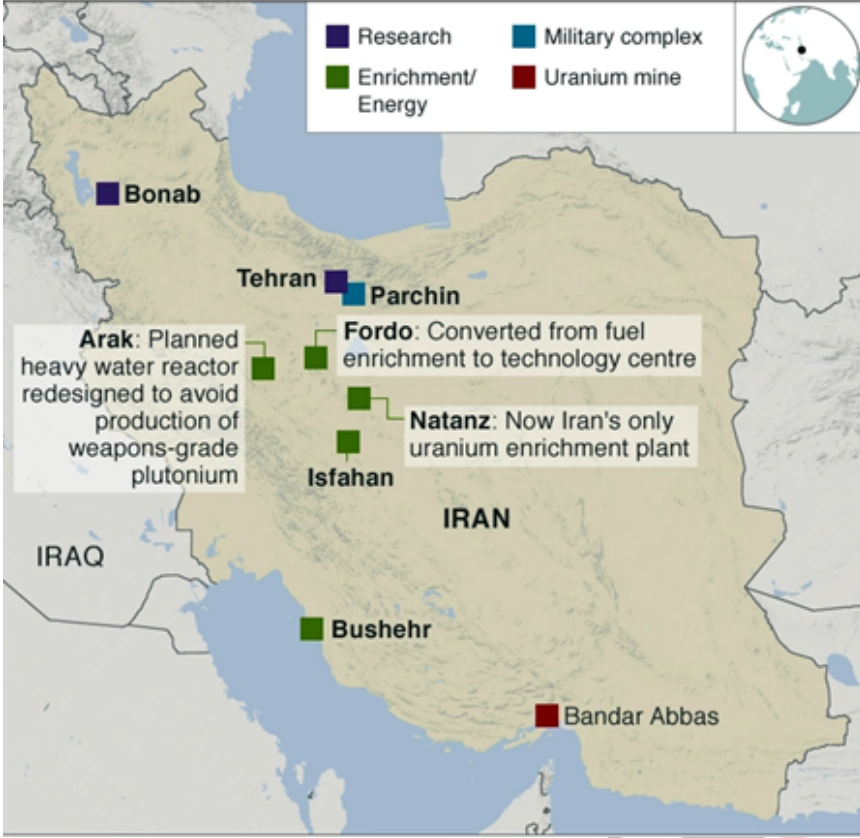
हाल ही में अमेरिका ने मुंबई स्थति एक पेट्रोकेमिकल कंपनी, तबालाजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड के खलिाफ प्रतबिंध लगाए क्योक़िउस पर ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों को बेचने का आरोप लगाया गया है ।

- **संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (JCPOA)** से अमेरिका के बाहर नकिलने के बाद वर्ष 2018-19 में पारति एकतरफा प्रतबिंधों के तहत अमेरिकी पदनाम का सामना करने वाली यह पहली भारतीय इकाई है ।

संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (JCPOA):

- इस समझौते को ईरान परमाणु समझौते, 2015 के नाम से भी जाना जाता है ।
- CPOA ईरान और P5+1 देशों (चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोपीय संघ या EU) के बीच वर्ष 2013-2015 के बीच चली लंबी बातचीत का परिणाम था ।
- ईरान एक प्रोटोकॉल को लागू करने पर भी सहमत हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के नरिीकषकों को अपने परमाणु स्थलों तक पहुँचने की अनुमति देगा ताकि यह सुनिश्चति हो सके कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार वकिसति नहीं कर रहा है ।
- हालाँकि पश्चिमि, ईरान के परमाणु प्रसार से संबंधति प्रतबिंधों को हटाने के लयि सहमत हो गया है, जबकि भिानवाधकारों के कथति हनन और ईरान के बैलसिटिकि मसिाइल कार्यक्रम को संबोधति करने वाले अन्य प्रतबिंध यथावत रहेंगे ।
- अमेरिका ने तेल नरियात पर प्रतबिंध हटाने के लयि प्रतबिद्धता व्यक्त की है, लेकिन वत्तीय लेन-देन को प्रतबिधति करना जारी रखा है जसिसे ईरान का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधति हुआ है ।
- बहरहाल ईरान की अर्थव्यवस्था मंदी, मुद्रा मूल्यहरास और मुद्रास्फीतति के बाद सौदे के प्रभावी होने के चलते काफी स्थरि हो गई तथा इसका नरियात भी काफी बढ़ गया है ।
- अमेरिका द्वारा वर्ष 2018 में सौदे को छोड़ने और बैकगि एवं तेल प्रतबिंधों को बहाल करने के बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा दिया, जो वर्ष 2015 से पहले की उसकी परमाणु क्षमताओं का लगभग 97% था ।

Changes agreed under Iran deal to limit nuclear programme



अमेरिका के इस सौदे से पीछे हटने के प्रभाव:

- अप्रैल 2020 में अमेरिका ने प्रतिबंधों को वापस लेने के अपने उद्देश्य की घोषणा की। हालाँकि अन्य भागीदारों ने इस कदम पर आपत्त जताते हुए कहा था, चूँकि अमेरिका अब इस सौदे का हिस्सा नहीं है, इसलिये वह एकतरफा प्रतिबंधों को फरि से लागू नहीं कर सकता था।
- शुरुआत में वापसी के बाद कई देशों ने ट्रंप प्रशासन द्वारा दी गई छूट के तहत ईरान से तेल का आयात करना जारी रखा। लगभग एक वर्ष बाद अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय आलोचनाओं के दबाव में छूट को समाप्त कर दिया और ऐसा करके ईरान के तेल निर्यात पर काफी हद तक अंकुश लगा दिया।
- अन्य शक्तियों ने, सौदे को बनाए रखने के प्रयास में, अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली के बाहर ईरान के साथ लेन-देन की सुविधा के लिये एक वस्तु वनिमिय प्रणाली शुरू की जसि **व्यापार वनिमिय के समर्थन में साधन (Instrument in Support of Trade Exchanges-INSTEX)** के रूप में जाना जाता है। हालाँकि INSTEX में केवल भोजन एवं दवा को कवर किया, जो पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों से मुक्त थे।
- जनवरी 2020 में अमेरिका द्वारा शीर्ष ईरानी जनरल कासमि सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने घोषणा की कि वह अब अपने यूरेनियम संवर्द्धन को सीमित नहीं करेगा।
- सितंबर 2022 में ईरान और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अधिकारियों ने रफिक्टरों की नगिरानी के लिये नरीकषकों को ईरान में वापस लाने के लिये ईरान के समझौते की संभावना पर चर्चा करने हेतु एक दौर को वारत्ता की।
 - अमेरिका और ईरान ने भी JCPOA में फरि से शामिल होने पर "अंतिम मसौदे" के लिये यूरोपीय संघ के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से अपने पक्ष का आदान-प्रदान किया है।

भारत के लिये संयुक्त व्यापक कार्ययोजना का महत्त्व:

- **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में वृद्धि:**
 - यदि प्रतिबंध हटा लिये जाते हैं तो बंदर अबबास और **चाबहार बंदरगाहों** के साथ-साथ क्षेत्रीय संपर्क की अन्य योजनाओं में भारत की **दलिचस्पी** फरि से पुनर्जीवित हो सकती है।
 - इससे भारत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर चीन की भूमिका को बेअसर करने में मदद मिलेगी।
 - चाबहार के अलावा ईरान से होकर गुजरने वाले **अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरडोर (INSTC)** में भारत की दलिचस्पी को भी बढ़ावा मिल सकता है, जो पाँच मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ संपर्क में सुधार करेगा।
- **ऊर्जा सुरक्षा:**
 - **काउंटरगि अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सैंकशनस एक्ट (CAATSA)** से जुड़े दबाव के कारण भारत को तेल आयात को शून्य पर लाना है।
 - अमेरिका और ईरान के बीच संबंधों की बहाली से भारत को ईरान से सस्ते तेल की खरीद करने तथा ऊर्जा सुरक्षा में सहायता करने में मदद मिलेगी।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन 'खाडी सहयोग परषिद' का सदस्य नहीं है? (2016)

- (a) ईरान
- (b) सऊदी अरब
- (c) ओमान
- (d) कुवैत

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- खाडी सहयोग परषिद (GCC) अरब प्रायद्वीप में 6 देशों- बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का गठबंधन है। **ईरान GCC का सदस्य नहीं है।**
- यह सदस्यों के बीच आर्थिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 1981 में स्थापति कया गया था तथा सहयोग एवं क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा करने के लिये प्रत्येक वर्ष एक शखिर सम्मेलन आयोजति करता है।

अतः वकिल्प (a) सही है।

[स्रोत: द हद्रि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/joint-comprehensive-plan-of-action>

